



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 20, 1965 (कार्तिक 29, 1887)

No. 47]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 20, 1965 (KARTIKA 29, 1887)

इस भाग में मिला पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paglug is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस

### NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 6 नवम्बर 1965 तक प्रकाशित किए गए थे :—

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 6th November 1965 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तारीख (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
150	No. 13 ETC(PN)/65, dt. 2-11-1965	Ministry of Commerce	Export of Garments and made up articles made from cotton handloom Fabric commonly known as "Bleeding Madras."
151	No. F.7(14)/-NS/65, dt. 3-11-65	Ministry of Finance	The Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Fourth Amendment Rules, 1965.
152	No. 14-ETC(PN)/65, dt. 3-11-65	Ministry of Commerce	Export of de-oiled ground nut cake (extractions).
153	No. 95-ITC(PN)/65, dt. 5-11-65	Do.	Import of refractories Ban on.
154	No. F. 34(8)/-NS/65, dt. 6-11-1965	Ministry of Finance	Declaration of second draw for prizes of the Premium Prize Bonds, 1964.
155	No. 14(29)-W & M/65, dt. 6th Nov. 1965	Do.	Amendment to notification No. F. 4(29)-W & M/65, dt. 19th October 1965 relating to National Defence Gold Bonds, 1980.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

### विषय-सूची (CONTENTS)

पृष्ठ (Pages)	पृष्ठ (Pages)
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं .. .. . 641	भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं .. .. . 65
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं .. .. . 979	भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं .. .. . 591
	भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .. .. . —
	भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रश्न समितियों की रिपोर्टें .. .. . —

	पृष्ठ (Pages)		पृष्ठ (Pages)
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ..	1743	भाग III—खंड 2—एकसूच कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें ..	417
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं .. .. .	3721	भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं ..	173
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .. .. .	295	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं ..	3069
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..	779	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	217
		पुरक सं० 47—	
		13 नवम्बर 1965 को समाप्त होने वाले सप्ताह की मज्जमारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्टें ..	1627
		23 अक्टूबर 1965 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़े ..	1643
<hr/>			
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. .. .	641	PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. ..	3721
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. .. .	979	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	295
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence .. .. .	65	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India .. .. .	779
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the Ministry of Defence .. .. .	591	PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	417
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations .. .. .	—	PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..	173
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills .. .. .	—	PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. .. .	3069
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1743	PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies .. ..	217
		SUPPLEMENT No. 47—	
		Weekly Epidemiological Reports for week-ending 13th November 1965 .. .. .	1627
		Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 23rd October 1965 .. .. .	1643

## भाग I—खण्ड 1

## PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

**Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court**

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर 1965

सं० 103-प्रेज/65—राष्ट्रपति मद्रास पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

**अधिकारियों के नाम तथा पद**

श्री रामसिंह रामचन्द्र सिंह,

हैड कान्स्टेबल सं० 350,

उत्तर मदुरई जिला,

मद्रास ।

(स्वर्गाय)

श्री जैकब देवराज,

पुलिस कान्स्टेबल सं० 644,

उत्तर मदुरई जिला,

मद्रास ।

(स्वर्गाय)

**सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किये गये**

12 फरवरी, 1965 को प्रातः यह सूचना मिली कि जुलूसों पर लगाई गई रोक के आदेश का उल्लंघन करने के लिये गुडालूर में एक जुलूस निकाले जाने की सम्भावना थी। जुलूस की सही स्थिति का पता लगाने के लिये हैड कान्स्टेबल रामसिंह रामचन्द्र सिंह वहां गये और उसने लगभग 1000 व्यक्तियों का एक जुलूस देखा जो बाद में 6000 का हो गया। हैड कान्स्टेबल ने उत्थमपालयम में सूचना भेजी। इतने में जुलूस की भीड़ हिंसा पर उतर आई और गुडालूर के डाकखाने पर आक्रमण कर दिया। हैड कान्स्टेबल तुरन्त थाने की ओर भागा और वहां पर स्थित पुलिस वालों को थाने की रक्षा के लिये तैयार होने को सावधान कर दिया।

उत्तेजित भीड़ थाने की ओर मुड़ी और पुलिस की डियूटी पर एक लारी को आग लगा दी। हैड कान्स्टेबल रामचन्द्र सिंह वहीं में नहीं था किन्तु उसने एक बन्दूक उठा ली और थाने की रक्षा के लिये अन्य पुलिस वालों के साथ सम्मिलित हो गया। पुलिस की गोलीबारी के बावजूद भीड़ ने थाने पर धावा बोल दिया, पुलिस वालों पर काबू पा लिया और उन्हें निहत्था कर थाने से बाहर निकाल दिया। हैड कान्स्टेबल रामचन्द्र सिंह और पुलिस कान्स्टेबल जैकब देवराज अपनी जगह पर डटे रहे। वे अनियमित भीड़ से लड़ते रहे और अन्ततः उपद्रवियों ने उन पर काबू पा लिया और उनकी हत्या कर दी।

इस प्रकार हैड कान्स्टेबल रामसिंह रामचन्द्र सिंह तथा कान्स्टेबल जैकब देवराज ने कर्तव्यपालन में उत्कृष्ट वीरता, उदाहरणीय कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हुए अपने जीवन न्योछावर कर दिये।

2. ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 फरवरी, 1965 से दिया जायेगा।

सं० 104-प्रेज/65—राष्ट्रपति मद्रास पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

**अधिकारी का नाम तथा पद**

श्री रामस्वामी गौण्डर मारियप्पन,

हैड कान्स्टेबल सं० 375,

कोयम्बतूर जिला,

मद्रास ।

**सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया**

10 फरवरी, 1965 को लगभग 600 विद्यार्थियों ने जुलूसों पर लगी रोक के आदेश की अवहेलना करके एक जुलूस निकाला। थोड़ी देर में स्थानीय गुण्डे उनमें शामिल हो गए और भीड़ की संख्या 6000 तक पहुंच गई। भीड़ ने डाकखाने पर हमला किया, कागजों को आग लगा दी, टेलीफोन और तार की तारें काट दीं और इस प्रकार भारी नुकसान किया। हैड कान्स्टेबल रामस्वामी गौण्डर मारियप्पन जो कि वेल्लाकोयल थाने का इंचार्ज था, उप-तहसीलदार और एक अन्य पुलिस कान्स्टेबल के साथ डाकखाने की तरफ दौड़ा। इतने में गुण्डे डाकखाने की छत पर चढ़ गए, छत उखेड़ दी और हैड कान्स्टेबल और उप-तहसीलदार जो अन्दर फंस गए थे, को जलाने के विचार से पेट्रोल छिड़का। हैड कान्स्टेबल मारियप्पन डाकखाने को बचाने के लिए बहानुरी से लड़ा और अनेकों चोटों के बावजूद उमड़ती हुई भीड़ को डेढ़ घंटे तक रोके रखा। अन्ततः वह उप-तहसीलदार को साथ लेकर बच निकलने में सफल हो गया और थाने में पहुंच गया।

हैड कान्स्टेबल रामस्वामी गौण्डर मारियप्पन ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अत्यन्त गम्भीर स्थिति में बड़े साहस, स्थिरता तथा उत्कृष्ट कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 फरवरी, 1965 से दिया जायेगा।

सं० 105-प्रेज/65—राष्ट्रपति आन्ध्र प्रदेश के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

**अधिकारियों के नाम तथा पद**

श्री कूर्लगुण्ड तिममरसु,

पुलिस उप-निरीक्षक,

ताड़पल्ली पुलिस थाना,

आन्ध्र प्रदेश ।

श्री कन्दुल डेविड,

स्टेशन अधिकारी,

ताड़पल्ली फायर स्टेशन,

आन्ध्र प्रदेश ।

श्री कायल पेहप्पा,  
फायरमैन सं० 267,  
ताड़पत्री फायर स्टेशन,  
आन्ध्र प्रदेश ।

#### सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किये गये

2 सितम्बर, 1964 को तीन स्त्रियां पेन्नार नदी के बीच में भूमि के एक टुकड़े पर खेती करने गईं। थोड़ी देर बाद नदी चढ़नी शुरू हो गई और इससे पहले कि स्त्रियां खतरे को महसूस कर सकें पानी कमर से ऊपर तक आ गया और जहाँ वे खड़ी थीं वहाँ से किनारे तक का पाट और भी गहरा था। स्त्रियों ने कुछ कांटेदार झाड़ियां पकड़ ली और सहायता के लिये चिल्लाना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर श्री कन्दुल डेविड, फायर स्टेशन अधिकारी एक चलते फिरते टैंक यूनिट पर घटनास्थल की ओर तुरन्त गये और श्री कूर्लगुण्ड तिममरसु, पुलिस उप-निरीक्षक भी कुछ कान्स्टेबलों के साथ वहाँ आ गये। सर्वश्री डेविड, तिममरसु तथा फायरमैन कायल पेहप्पा तीनों निस्सहाय स्त्रियों को बचाने के लिये लाइफवायस लेकर नदी में घुस गये। बाढ़ के पानी की तेज़ धारा की परवाह न करते हुए तीनों अधिकारी उन स्त्रियों तक पहुँचने में सफल हो गए। सर्वश्री डेविड तथा तिममरसु ने दो स्त्रियों को बचा लिया जबकि फायरमैन तीसरी थकी हुई औरत को सहारा देने के लिये वहीं रह गये। तब दोनों अधिकारी तीसरी स्त्री को बचाने के लिए वापस आये। वापसी पर उन्होंने दो और व्यक्तियों को भी बचाया जो बाढ़ के कारण वहाँ फंस गये थे।

इस कार्यवाही के दौरान श्री कूर्लगुण्ड तिममरसु, श्री कन्दुल डेविड तथा श्री कायल पेहप्पा ने वीरता और उच्च-स्तर की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 सितम्बर, 1964 से दिया जायेगा।

सं० 106-प्रेज/65—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

#### अधिकारी का नाम तथा पद

श्री शेखरानन्द नैथानी,  
कम्पनी-सैकण्ड-इन्-कमांड,  
डी कम्पनी, 12वीं बटालियन,  
मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र दल।

#### सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

27 जुलाई 1964 को लगभग 200 विद्रोहियों ने विशेष सशस्त्र दल तथा नागालैण्ड सशस्त्र पुलिस की चुचुयिमलांग स्थित चौकियों पर हमला कर दिया। विद्रोहियों ने 51 मशीन-गनों, 2" मार्टिन, जी० एफ० राइफलें, हल्की एवं मशीनली मशीन-गनों का प्रयोग किया। श्री शेखरानन्द नैथानी, कम्पनी-सैकण्ड-इन्-कमांड ने अपने जवानों को भिन्न-भिन्न मोर्चों को संभालने और विद्रोहियों पर गोलीबारी करने का आदेश दिया। विद्रोहियों की भारी गोलीबारी के बावजूद श्री नैथानी ने मानसिक संतुलन बनाये रखा और अपने जवानों की वीरता से विद्रोहियों का सामना करने के लिये उत्साहित करते रहे। विद्रोहियों की दो टुकड़ियाँ, अपनी शारीरिक बनावट तथा अंधेरे का लाभ उठा कर, चौकी से 30 गज दूरी तक रेंग कर बढ़ आईं। पुलिस की टुकड़ियों को सभी ओर से उलझाए रख कर विद्रोही नागालैण्ड सशस्त्र पुलिस चौकी तक आ गए और उनसे आत्मसमर्पण की मांग की। स्थिति की गम्भीरता और जरूरत को अनुभव करते हुए श्री नैथानी ने बाहर आने और नज़दीक के विद्रोही दल पर हथगोलों

से हमला करने का फैसला किया। ऐसा करके वह विद्रोहियों की भारी गोलीबारी के सामने खुले में आ गया। इस साहसिक कार्य-वाही ने विद्रोहियों की अगली पांत को तितर-बितर कर दिया। उसी समय दूसरे विद्रोही दल पर संतरी की चौकी से हल्की मशीन-गनों से सही निशाने किये गये। श्री नैथानी ने तब नागालैण्ड पुलिस चौकी की मदद के लिये दो टुकड़ियाँ भेजीं जिसने विद्रोहियों की हल्की मशीनगनों को खामोश कर दिया और विद्रोहियों के आक्रमण को विफल बना दिया।

इस कार्यवाही में श्री शेखरानन्द नैथानी ने उदाहरणीय साहस तथा उच्च-स्तर के नेतृत्व का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27 जुलाई, 1964 से दिया जायेगा।

सं० 107-प्रेज/65—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सुरक्षित पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

#### अधिकारी का नाम तथा पद

श्री लेख सिंह,  
कान्स्टेबल सं० 3331,  
उरी बटालियन,  
केन्द्रीय सुरक्षित पुलिस।

#### सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

18 अगस्त, 1965 को लगभग 60 पाकिस्तानी घुसपैठियों के एक गिरोह ने बेयिल पर श्रीनगर लेह की युद्धोपयोगी सड़क को काटने का असफल प्रयत्न किया। बेयिल पुल को नष्ट करने की चेष्टा में घुसपैठियों ने इस प्रमुख सड़क पुल पर तैनात केन्द्रीय सुरक्षित पुलिस की छोटी चौकी पर आक्रमण किया।

रात के 3.00 बजे के करीब कान्स्टेबल लेख सिंह ने, जो संतरी डिप्टी पर था, पुल के क्षेत्र में संदेहास्पद शोर सुना और गारद को जो वहाँ से 20 गज दूर एक मकान में थी, सावधान किया, अंधेरे में दो घुसपैठिये संतरी चौकी के बहुत निकट आ गए और कान्स्टेबल लेख सिंह पर हथगोले फेंके। सौभाग्यवश हथगोले थोड़ी दूरी पर फटे। कान्स्टेबल लेख सिंह ने तुरन्त प्रतिकार किया और दोनों घुसपैठियों को गोली से उड़ा दिया। थोड़ी देर बाद लगभग 60 घुसपैठिये चुपके से पुल पर पहुँचे और स्वचालित हथियारों से संतरी चौकी और गारद स्थित मकान पर आक्रमण कर दिया। बावजूद इसके कि कान्स्टेबल लेख सिंह गारद के मुख्य दस्ते से दूर था और केवल 303 से लैस था, उसने संख्या में बहुत अधिक शत्रुओं का निर्भीकता से तब तक सामना किया जब तक कि हमलावर नज़दीक के जंगल में नहीं भाग गए।

कान्स्टेबल लेख सिंह ने उत्कृष्ट वीरता, पहलशक्ति तथा उच्चतम स्तर की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 अगस्त, 1965 से दिया जायेगा।

सं० 108-प्रेज/65—राष्ट्रपति केन्द्रीय सुरक्षित पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

#### अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रिसाल सिंह,  
कान्स्टेबल सं० 3013,  
उरी बटालियन,  
केन्द्रीय सुरक्षित पुलिस।

**सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया**

18 अगस्त, 1965 को लगभग 60 पाकिस्तानी घुसपैठियों के एक गिरोह ने वेयिल पर श्रीनगर लेह की युद्धोपयोगी सड़क को काटने का असफल प्रयत्न किया। वेयिल पुल को नष्ट करने की चेष्टा में घुसपैठियों ने इस प्रमुख सड़क पुल पर तैनात केन्द्रीय सुरक्षित पुलिस की छोटी चौकी पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि केन्द्रीय सुरक्षित पुलिस की टुकड़ी संख्या में बहुत कम थी फिर भी उसने बलशाली प्रतिकार किया और अन्ततः सुनियोजित आक्रमण को पिछाड़ दिया।

भारी गोलीबारी के आदान-प्रदान के दौरान कान्स्टेबल रिसाल सिंह का हाथ जखमी हो गया इस घोट की परवाह न करते हुए कान्स्टेबल रिसाल सिंह ने तब तक लड़ना जारी रखा जब तक कि हमलावर नजदीक के जंगल में भाग नहीं गये। दोपहर बाद जब घुसपैठियों ने केन्द्रीय सुरक्षित पुलिस की चौकी पर पुनः भारी गोलीबारी की तब श्री रिसाल सिंह ने शत्रु के विरुद्ध कार्यवाही में सक्रिय भाग लिया।

यद्यपि कान्स्टेबल रिसाल सिंह जखमी हो गया था फिर भी उसने शत्रु से लड़ना जारी रखा और उच्च-स्तर की कर्तव्य-परायणता की भावना का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 अगस्त, 1965 से दिया जायेगा।

सं० 109-प्रेज/65—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सुरक्षित पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं:—

**अधिकारी का नाम तथा पद**

श्री रमेश भोपा,  
कान्स्टेबल सं० 2587,  
3री बटालियन,  
केन्द्रीय सुरक्षित पुलिस

**सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया**

18 अगस्त, 1965 को लगभग 60 पाकिस्तानी घुसपैठियों के एक गिरोह ने वेयिल पर श्रीनगर लेह की युद्धोपयोगी सड़क को काटने का असफल प्रयत्न किया। वेयिल पुल को नष्ट करने की चेष्टा में घुसपैठियों ने इस प्रमुख सड़क पुल पर तैनात केन्द्रीय सुरक्षित पुलिस की छोटी चौकी पर आक्रमण किया। यद्यपि केन्द्रीय सुरक्षित पुलिस की टुकड़ी संख्या में बहुत कम थी फिर भी उसने बलशाली प्रतिकार किया और अन्ततः सुनियोजित आक्रमण को पिछाड़ दिया।

आक्रमण के समय कान्स्टेबल रमेश भोपा गारद स्थित भकान के बाहर एक कच्चे बन्कर में अकेला था। घुसपैठियों की भारी गोलीबारी की परवाह न करते हुए कान्स्टेबल भोपा अपने बन्कर में डटा रहा और शत्रु की भारी गोलीबारी का सामना तब तक करता रहा जब तक कि शत्रु नजदीक के जंगल में भाग जाने पर विवश न हो गये।

कान्स्टेबल रमेश भोपा ने वीरता और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 अगस्त, 1965 से दिया जायेगा।

सं० 110-प्रेज/65—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सुरक्षित पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं:—

**अधिकारी का नाम तथा पद**

श्री राम कृपाल राय,  
नायक सं० 2891,  
3 री बटालियन,  
केन्द्रीय सुरक्षित पुलिस।

**सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया**

18 अगस्त, 1965 को लगभग 60 पाकिस्तानी घुसपैठियों के एक गिरोह ने वेयिल पर श्रीनगर लेह की युद्धोपयोगी सड़क को काटने का असफल प्रयत्न किया। वेयिल पुल को नष्ट करने की चेष्टा में घुसपैठियों ने इस प्रमुख सड़क पुल पर तैनात केन्द्रीय सुरक्षित पुलिस की छोटी चौकी पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि केन्द्रीय सुरक्षित पुलिस की टुकड़ी संख्या में बहुत कम थी फिर भी उसने बलशाली प्रतिकार किया और अन्ततः सुनियोजित आक्रमण को पिछाड़ दिया।

घुसपैठियों द्वारा हल्की और मझोली मशीनगनों और अन्य स्वचालित हथियारों से की गई भारी गोलीबारी के दौरान नायक रामकृपाल राय एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे और छाइयों में स्थित जवानों को शत्रु का सामना करने के लिये उत्साहित करते रहे। इस कार्यवाही के दौरान वह कई बार शत्रु की गोलियों के सामने खुले में आये। नायक राम कृपाल राय के सुयोग्य नेतृत्व में केन्द्रीय सुरक्षित पुलिस की छोटी टुकड़ी ने शत्रु की एक ताकतवर टुकड़ी के कपट से किये गए हमले को सफलतापूर्वक पिछाड़ दिया।

इस प्रकार नायक राम कृपाल राय ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की ज़रा भी परवाह न करते हुए वीरता तथा उच्च-स्तर की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 अगस्त, 1965 से दिया जायेगा।

वाई० डी० गण्डेविया, राष्ट्रपति के सचिव

**बाणिज्य मंत्रालय****संकल्प**

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 1965

सं० 12/31/65-ई० प्रापर—भारत रक्षा नियम 1962 के नियम 133-बी के उप-नियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करती हुई केन्द्रीय सरकार सहर्ष आदेश देती है कि मे० मोखामादीन एण्ड सन्स लि०, कलकत्ता की भारत में समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति जो कि उनकी है, जो उनके पास है या जिसका प्रबन्ध उनकी ओर से किया जाता है भारत शत्रु सम्पत्ति परीक्षक के अधिकार में चली जायेगी।

पी० के० जे० मेनन, संयुक्त सचिव

**लौह अयस्क निर्यात (प्रायोजना) समिति****संकल्प**

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 1965

सं० 15/66/64-एम० एण्ड एफ०—भारत सरकार के संकल्प संख्या 15/66/64-एम० एण्ड एफ० दिनांक 3 अक्टूबर, 1964 में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार ने निश्चय किया है कि उपर्युक्त समिति के गठन से सम्बन्धित संकल्प के पैरा 3 में श्री डी० एन० बनर्जी, संयुक्त सचिव, बाणिज्य मंत्रालय के स्थान

पर वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री एस० के० मुखर्जी का नाम सदस्य सचिव के रूप में परिस्थापित किया जाए।

#### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के गजट में प्रकाशित किया जाए।

एस० हामिद, संयुक्त सचिव

### लौह अयस्क निर्यात (प्रायोजना) समिति

#### संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्टूबर 1964

सं० 15/49/64-एम० एण्ड एफ०—लौह अयस्क निर्यात के विकास कार्यक्रम के अनुसरण में भारत सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी जिसने खनन, परिवहन, पत्तन कार्यों तथा लौह-अयस्क के निर्यात/बिक्री के विकास के लिए विस्तृत समन्वित प्रायोजना तैयार की।

इस कार्यक्रम को, जिसका परिचालन समस्त रूप से अब वाणिज्य मंत्रालय के अधीन किया जाएगा, कार्यान्वित करने के लिए एक केन्द्रीय समिति की स्थापना की गई है।

#### 2. नाम :—

समिति का नाम “लौह अयस्क निर्यात (प्रायोजना) समिति” होगा।

#### 3. समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा :—

##### अध्यक्ष

श्री गोविन्द नारायण, अध्यक्ष, धातु तथा खनिज व्यापार निगम।

##### सदस्य

डा० नगेन्द्र सिंह, महानिदेशक, नौवहन।

श्री आर० एन० वासुदेवा, संयुक्त सचिव, इस्पात तथा खनिज मंत्रालय।

श्री के० एन० श्रीनिवासन, विकास सलाहकार (पत्तन) परिवहन मंत्रालय।

श्री के० नारायणन, उप-सचिव, परिवहन मंत्रालय।

श्री जगजीत सिंह, निदेशक (परिवहन), रेलवे बोर्ड।

श्री एम० एन० बेरी, निदेशक (योजना), रेलवे बोर्ड।

श्री एस० एन० बिलग्रामी, अध्यक्ष एन०एम० १० सी०।

##### सदस्य-सचिव

श्री डी० एन० बैनर्जी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय।

#### कार्य :

(1) समिति, लौह-अयस्क प्रायोजना की सभी खनिज रेल तथा पत्तनों के विकास सम्बन्धी गतिविधियों का समन्वय करेगी और लौह-अयस्क के दीर्घकालिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगी। समिति वाणिज्य मंत्रालय को नियमपूर्वक प्रतिमास अपनी रिपोर्टें देती रहेगी।

(2) इस प्रायोजना को कार्यान्वित करने के लिए समिति को आवश्यक विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त होगी और यह समिति इस प्रायोजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी जिसके लिए उसे भारत सरकार की ओर से कार्य करने का अधिकार होगा।

(3) समिति अपने ध्येयों की प्राप्ति के लिए किसी भी सम्बन्धी क्षेत्र अथवा बाजार का अध्ययन करने में आवश्यक अनुसंधान कराने अथवा इस्पात उद्योग के किन्हीं भी रुखों या संसार के लौह अयस्क कार्यक्रमों के अध्ययन करने के लिए सक्षम होगी।

(4) लौह-अयस्क के विभिन्न कार्यक्रमों में समिति विभिन्न सम्बद्ध राज्य सरकारों का सहयोग तथा आवश्यक सक्रिय योगदान भी प्राप्त कर सकेगी।

(5) अपने कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए समिति समय-समय पर एक अथवा अधिक सलाहकार समितियाँ नियुक्त कर सकती है।

(6) ‘प्रायोजना’ के विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए समिति परीक्षण विमर्श तथा देखरेख जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सहायता के लिए सक्षम विशेषज्ञों के उपयुक्त पदों जैसे कि : खनन इंजीनियरों, यांत्रिक इंजीनियरों, पत्तन इंजीनियरों, विपणन अनुसंधान अधिकारियों, लागत तथा वित्त अधिकारियों आदि को बना सकेगी।

#### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये :

डी० एन० बनर्जी, संयुक्त सचिव

### लौह अयस्क निर्यात (प्रायोजना) समिति

#### संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्टूबर 1965

सं० 15/66/64-एम० एण्ड एफ०—भारत सरकार के संकल्प सं० 15/49/64-एम० एण्ड एफ० दिनांक 3 अक्टूबर, 1964 जो कि इसी संख्या तथा दिनांक 15 फरवरी, 1965 के संकल्प द्वारा संशोधित किया गया है, उसमें और भी संशोधन करते हुए भारत सरकार ने निश्चय किया है कि इस समिति के गठन से सम्बन्धित संकल्प के पैरा 3 में निम्न संशोधन तथा परिवर्धन किया जाए :—

(1) रेलवे बोर्ड के निदेशक (परिवहन) श्री जगजीत सिंह के स्थान पर रेलवे बोर्ड के निदेशक, यातायात (परिवहन) श्री जी० एस० खोसला के नाम की परिस्थापना की जाए।

(2) श्री एस० के० मुखर्जी के नाम के ऊपर श्री के० एल० लूथरा, निदेशक, परिवहन प्रभाग, योजना आयोग, का नाम ‘सदस्य के रूप में’ जोड़ दिया जाए।

#### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के गजट में प्रकाशित किया जाए।

एस० के० मुखर्जी, संयुक्त सचिव

### शिक्षा मंत्रालय

#### संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 4 नवम्बर 1965

सं० एफ० 1-12/65 एच० 1—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० 1-12/56 एच० 1, तारीख 4 जुलाई, 1957 जैसा कि संकल्प संख्या एफ०-1-4/59-एच० 1, तारीख 16 अक्तूबर, 1959 तथा संख्या एफ० 1-3/62-एच० 1, तारीख 19 दिसम्बर, 1962 द्वारा संशोधन किया गया है, को रद्द करते हुये यह निश्चय किया जाता है कि 1 नवम्बर 1965 से हिन्दी शिक्षा समिति का गठन तथा कार्य निम्न प्रकार से होंगे :—

#### 1. संगठन

(i) अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री

(ii) उपाध्यक्ष, शिक्षा मंत्रालय में भाषा प्रभाग के कार्यभारी मंत्री

(iii) प्रत्येक संघीय राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों तथा राज्य सरकारों का एक-एक प्रतिनिधि जो शिक्षा निदेशक के ओहदे के बराबर का अधिकारी होगा।

(iv) लोक सभा से चार सदस्य जो अध्यक्ष (स्पीकर) द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

(v) राज्य सभा से दो सदस्य जो राज्य सभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

(vi) प्रमुख स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों के पांच प्रतिनिधि जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

- (vii) हिन्दी प्रचार के कार्य में रुचि रखने वाले पांच प्रमुख कार्यकर्ता जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।
- (viii) शिक्षा मंत्रालय के भाषा प्रभाग कार्यभारी संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव सलाहकार।
- (ix) अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग।
- (x) निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय।
- (xi) गृह मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।
- (xii) अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा।
- (xiii) शिक्षा मंत्रालय के भाषा प्रभाग में कार्यभारी उप-सचिव/उप-शिक्षा सलाहकार।

—सचिव

## 2. कार्यकाल

समिति के सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि 3 वर्ष की होगी जो नियुक्ति के वर्ष की 1 जनवरी से गिनी जायेगी किन्तु,

- (i) उप-धारा 1 (iv), 1 (v) और 1 (vii) के अधीन मनोनीत सदस्य जैसे ही वह संसद् की सदस्यता, केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा की अध्यक्षता से हटता है, जैसा भी मामला हो, समिति का सदस्य नहीं रहेगा।
- (ii) समिति के पदेन सदस्य तब तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे उस पद पर कार्य करते रहेंगे जिसके कारण वे समिति के सदस्य हैं।
- (iii) अन्य मनोनीत सदस्य भारत सरकार की इच्छानुसार अपने-अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे; और
- (iv) यदि किसी सदस्य के त्याग-पत्र, मृत्यु आदि के कारण कोई स्थान रिक्त होता है तो उस रिक्त स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य तीन वर्ष की अवशेष अवधि तक कार्य करता रहेगा।

## 3. कार्य

समिति भारत सरकार को निम्नलिखित विषयों पर परामर्श देगी :—

- (i) देश में हिन्दी के प्रचार तथा प्रसार से संबंधित नीति के मामले;
- (ii) विभिन्न स्तरों पर हिन्दी शिक्षा की पद्धतियों, पाठ्य-चर्याओं का मानकीकरण और हिन्दी अध्ययन के पाठ्य-क्रमों का समन्वय जिनमें हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण, संस्थाओं के पाठ्यक्रम, हिन्दी अध्यापकों की योग्यताएँ

और अहिन्दी भाषी राज्यों के लिये हिन्दी अध्यापकों का प्रशिक्षण भी शामिल है;

- (iii) केन्द्रीय सरकार की सहायता से विभिन्न अहिन्दी भाषी राज्यों में खोले गये हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण कालेजों के सुधार के लिये अपनाई जाने वाली पद्धतियाँ;
- (iv) देश में विभिन्न स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों द्वारा चलायी जाने वाली परीक्षाओं की मान्यता;
- (v) हिन्दी प्रचार के लिए अहिन्दी भाषी प्रान्तों में काम करने वाले विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के कार्य-कलापों में समन्वय; और
- (vi) अहिन्दी भाषी राज्यों के स्कूलों, कालेजों तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों में मुफ्त वितरण के लिये हिन्दी पुस्तकों का चुनाव।

## 4. समिति की स्थायी समितियाँ

अपने विभिन्न कार्यों को सुचारु रूप से चला सकने के लिए और कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए समिति कुछ स्थायी समितियाँ नियुक्त कर सकती है जिनमें से निम्नलिखित तीन अनिवार्य हैं :—

- (i) हिन्दी विकास के लिए स्थायी समिति;
- (ii) हिन्दी प्रचार के लिए स्थायी समिति; और
- (iii) हिन्दी शिक्षण तथा परीक्षाओं के लिए स्थायी समिति।

साधारण रूप से स्थायी समिति में अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों से अधिक सदस्य नहीं होंगे। तो भी, समितियों को उन व्यक्तियों को सहयोजित करने का अधिकार होगा, जो या तो समिति के सदस्य हैं अथवा समिति के सदस्य नहीं हैं किन्तु जिन्हें विशिष्ट ज्ञान तथा समस्याओं का अनुभव है।

## आवेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों तथा संघीय प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक-सभा, राज्य-सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाय।

रामस्वरूप चितकारा, उप-शिक्षा सलाहकार

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 11th November 1965

No. 103./65.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madras Police :—

### Name of the officers and rank

Shri Ramsingh Ramachandra Singh,  
Head Constable No. 350, Madurai North District,  
Madras. (Deceased)

Shri Jacob Devaraj,  
Police Constable No. 644, Madurai North District,  
Madras. (Deceased)

Statement of services for which the decorations have been awarded.

On the morning of 12th February 1965, information was received that a procession was likely to be taken in Gudalur in violation of the prohibitory order. In order to find out the exact position of the procession, Head Constable Ramsingh Ramachandra Singh went there and found a procession of about 1,000 persons which later swelled to about 6,000. Head Constable communicated the information to Uthama-palayam. Meanwhile the processionists turned violent and attacked the Post Office at Gudalur. The Head Constable immediately rushed to the Police Station and alerted the policemen stationed there to be ready to defend the Police Station.

The violent mob turned towards the Police Station and set fire to a lorry engaged by the Police. Head Constable Ramchandra Singh was in *mufli*, but he picked up a musket and joined the other policemen in defending the Post. The mob invaded the Police Station despite firing by the police, overpowered and disarmed the policemen and drove them away. Head Constable Ramachandra Singh and Police Constable Jacob Devaraj remained at their posts. They continued to fight the unruly mob and were eventually overpowered and murdered by the rioters.

Thus Head Constable Ramchandra Singh and Constable Jacob Devaraj exhibited conspicuous gallantry, exemplary devotion to duty in the performance of which they lost their lives.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 12th February 1965.

No. 104-Pres./65.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Madras Police :—

### Name of the officer and rank

Shri Ramaswamy Gounder Mariappan.  
Head Constable No. 376,  
Coimbatore District,  
Madras.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

On the 10th February 1965, about 600 students took out a procession in defiance of the prohibitory order. Soon after the students were joined by local hooligans and the mob swelled to 6,000. The mob attacked the Post Office, set fire to the records, cut the telephone and telegraph wires and caused heavy damage. Head Constable Ramaswamy Gounder Mariappan, who was in charge of Vellakott Station rushed to the Post Office with the Deputy Tahsildar and another Police Constable. Meanwhile the rowdy elements got over the roof of the Post Office, removed the tiles and poured in petrol with a view to burning the Head Constable and the Deputy Tahsildar who were caught inside. Head Constable Mariappan put up a heroic fight to save the Post Office and despite many injuries kept the surging crowd at bay for nearly one and a half hours. Eventually he managed to extricate himself and the Deputy Tahsildar and reached the Police Station.

Head Constable Ramaswamy Gounder Mariappan displayed great courage, coolness and conspicuous devotion to duty in a most dangerous situation with regard for his own safety.

2. This award is made under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 10th February 1965.

No. 105-Pres./65.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the following officers of the Andhra Pradesh :—

*Names of the officers and rank*

Shri Kurlagunda Thimmarasu,  
Sub-Inspector of Police,  
Tadpatri Town Police Station,  
Andhra Pradesh.

Shri Kandula David,  
Station Officer,  
Tadpatri Fire Station,  
Andhra Pradesh.

Shri Kayala Peddappa,  
Fireman No. 267,  
Tadpatri Fire Station,  
Andhra Pradesh.

*Statement of Services for which the decoration has been awarded.*

On the 2nd September 1964, three women went to a piece of land in the middle of the river Pennar for agricultural operations. Soon after the river started rising and before the women could realise the danger, the water had risen to more than waist level where the women were standing and was much deeper in the channels between them and the banks. The women clutched some thorny shrubs and began to shout for help. On receipt of the information Shri Kandula David, Fire Station Officer, immediately rushed to the spot with a Mobile Tank Unit and Shri Kurlagunda Thimmarasu, Sub-Inspector of Police also came with some Constables. Sarvashri David, Thimmarasu and Fireman Kayala Peddappa plunged into the river with lifebouys to rescue the three helpless women. Undeterred by the strong current of the flood water, the three officers managed to reach the women. Sarvashri David and Thimmarasu first rescued two women while the Fireman remained behind to hold the third who was in a state of exhaustion. Then the two officers returned to rescue the third woman. On their way back they also rescued two other persons who had been stranded by the flooded river.

During this operation Shri Kurlagunda Thimmarasu, Shri Kandula David, and Shri Kayala Peddappa, exhibited gallantry and devotion to duty of a high order.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd September 1964.

No. 106-Pres./65.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police :—

*Name of the Officer and rank*

Shri Shekharanand Naithani,  
Company-Second-in-Command,  
'D' Company, 12th Battalion,  
Madhya Pradesh Special Armed Force.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

On the 27th July 1964, about 200 hostiles attacked the S.A.F. Post and Nagaland Armed Police Post at Chuchuyimlong. The hostiles used 51 MM guns, 2" mortar guns, G. F. Rifles, L.M.Gs. and MMGs. Shri Shekharanand Naithani, Company-Second-in-Command, ordered his men to take various positions and directed fire at the hostiles. In spite of heavy hostile fire Shri Naithani kept cool and encouraged his men to face the hostiles gallantly. Two

parties of the hostiles managed to creep up to 30 yards from the post taking advantage of physical features and darkness. Keeping the police parties engaged from all sides, the hostiles closed in on the Nagaland Armed Police Post and demanded their surrender. Realising the danger of the situation and its urgency, Shri Naithani decided to move out and attacked the nearest hostile party with grenades. In doing so he exposed himself to the heavy hostile fire. This bold action unsettled the hostiles' forward column. At the same time the second nearest hostile party was subjected to accurate LMG fire from the sentry post. Shri Naithani then sent two parties to the aid of the Nagaland Police Post who were able to silence the hostile LMGs and the hostile attack was broken up.

In this action Shri Shekharanand Naithani showed exemplary courage and leadership of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 27th July 1964.

No. 107-Pres./65.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police :—

*Name of the Officer and rank*

Shri Lekh Singh,  
Constable No. 3331,  
III Battalion,  
Central Reserve Police.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

On the 18th August 1965, a group of about 60 Pakistani infiltrators unsuccessfully tried to cut the strategic Srinagar Leh Road at Wayil. In a bid to damage the Wayil Bridge, the infiltrators attacked the small C.R.P. post guarding this important road bridge.

At about 0300 hours Constable Lekh Singh, who was on sentry duty, heard suspicious noises in the vicinity of the bridge and alerted the guard which was in a house 20 yards away. In the darkness, two infiltrators came very close to the sentry post and threw hand-grenades at Constable Lekh Singh. Fortunately the grenades exploded a little distance away. Constable Lekh Singh promptly retaliated and shot the two infiltrators dead. Soon after about 60 infiltrators stealthily approached the bridge and attacked the sentry post and the guard house with automatic weapons. In spite of the fact that he was far away from the main section of the guard and was only armed with a .303 rifle, Constable Lekh Singh faced the numerically superior enemy boldly till the raiders retreated to the nearby jungles.

Constable Lekh Singh exhibited conspicuous gallantry, initiative and devotion to duty of the highest order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 18th August 1965.

No. 108-Pres./65.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police :—

*Name of the Officer and rank*

Shri Risal Singh,  
Constable No. 3013,  
III Battalion,  
Central Reserve Police.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

On the 18th August 1965, a group of about 60 Pakistani infiltrators unsuccessfully tried to cut the strategic Srinagar Leh Road at Wayil. In a bid to damage the Wayil Bridge the infiltrators attacked the small C.R.P. post guarding this important road bridge. Although very much out-numbered the small C.R.P. party retaliated vigorously and eventually repulsed the well planned attack.

During heavy exchange of fire Constable Risal Singh was wounded in the hand. Undaunted by this injury, Constable Risal Singh continued to fight till the raiders retreated to the nearby jungles. When the infiltrators again opened heavy fire at the CRP post in the afternoon, Shri Risal Singh took an active part in action against the enemy. Although wounded, Constable Risal Singh continued to fight the enemy and exhibited high sense of duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 18th August 1965.



No. 109-Pres./65.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police :—

*Name of the officer and rank*

Shri Ramesh Bhopa,  
Constable No. 2587,  
III Battalion,  
Central Reserve Police.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

On the 18th August 1965, a group of about 60 Pakistani infiltrators unsuccessfully tried to cut the strategic Srinagar Leh Road at Wayil. In a bid to damage the Wayil Bridge, the infiltrators attacked the small C.R.P. post guarding this important road bridge. Although very much out-numbered the small C.R.P. party retaliated vigorously and eventually repulsed the well planned attack.

At the time of the attack Constable Ramesh Bhopa was alone in a kucha bunker outside the guard house. Undeterred by the heavy firing from the infiltrators, Constable Bhopa remained at his post and continued to return the heavy fire till the enemy was forced to retreat to the nearby jungle.

Constable Ramesh Bhopa exhibited gallantry and exemplary devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 18th August 1965.

No. 110-Pres./65.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police :—

*Name of the officer and rank*

Shri Ram Kirpal Rai,  
Naik No. 2891,  
III Battalion,  
Central Reserve Police.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

On the 18th August 1965, a group of about 60 Pakistani infiltrators unsuccessfully tried to cut the strategic Srinagar Leh Road at Wayil. In a bid to damage the Wayil Bridge the infiltrators attacked the small C.R.P. post guarding this important road bridge. Although very much out-numbered the small C.R.P. party retaliated vigorously and eventually repulsed the well planned attack.

During the heavy and concentrated fire by the infiltrators who were using LMGs, MMGs and other automatic weapons. Naik Ram Kirpal Rai moved continuously from one position to another and encouraged his men in the trenches to face the enemy. In doing so he exposed himself to the enemy fire many times. Under the able leadership of Naik Ram Kirpal Rai, the small party of CRP successfully repulsed the treacherous attack by a strong enemy party.

Naik Ram Kirpal Rai exhibited gallantry and devotion to duty of a high order in utter disregard for his personal safety.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 18th August 1965.

Y. D. GUNDEVIA, Secy. to the President.

## MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 3rd November 1965

No. 12/31/65-E.Pty.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 133-V of the Defence of India Rules, 1962 the Central Government is pleased to order that all property in India, moveable and immoveable, belonging to, or held by, or managed on behalf of Messrs. Mokhammadin & Sons Ltd., Calcutta, shall vest in the Custodian of Enemy Property for India.

P. K. J. MENON, Jt. Secy.

## MINISTRY OF INDUSTRY AND SUPPLY

(Department of Industry)

New Delhi, the 3rd November 1965

No. 7/8/65-SSI(C)(.)—In continuation of this Ministry's notification No. 7/8/65-SSI(C) dated the 19th May 1965, the President is pleased to extend the duration of the Public Works Divisions referred to therein as follows :—

- |  |  |
|--|--|
| (1) Northern S.S.I. Works Division, New Delhi. | 1st September, 1965 to the 28th February 1966. |
| (2) Western S.S.I. Works Division, Bombay.     |  |
| (3) Southern, S.S.I. Works Division, Madras.   |  |
| (4) Eastern S.S.I. Works Division, Calcutta.   |  |

L. G. MIRCHANDANI, Dy. Secy.

## MINISTRY OF HEALTH

### RESOLUTION

New Delhi, the 10th November 1965

No. F. 12-28/63-F.P.II.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. F. 12-28/63-FP.II dated the 28th August 1965, regarding constitution etc. of the Family Planning Programme Evaluation and Planning Committee, it has now been decided that the Committee will submit their report by the 31st December 1965, instead of the 31st October 1965.

M. K. KUTTY, Dy. Secy.

### RESOLUTION

New Delhi, the 10th November 1965

No. F. 4-52/65-FP.II.—In partial modification of the Government of India Ministry of Health Resolution No. 4-36/60-FP.II dated the 18th August 1965, regarding Constitution of the Central Family Planning Council, it has been decided to include Lt. Colonel B. L. Raina, Director, Central Family Planning Institute, New Delhi, as a member of the Council.

BASHESHA NATH, Under Secy.

## MINISTRY OF EDUCATION

### RESOLUTION

New Delhi, the 4th November 1965

No. F.1-12/65-H.J.—In supersession of this Ministry's Resolution No. F.1-12/56-H.I., dated the 4th July 1957, as amended by Resolution No. F.1-4/59-H.I. dated the 16th October 1959 and No. F.1-3/62-H.I. dated the 19th December 1962, it is hereby resolved that with effect from the 1st November 1965, the composition and functions of the Hindi Shiksha Samiti shall be as follows :—

#### 1. Composition

- (i) Chairman, Minister of Education.
- (ii) Vice-Chairman, Minister Incharge of the Languages Division in the Ministry of Education.
- (iii) One representative each of the State Governments and Administrations of Union Territories who shall be an officer not below the rank of Director of Education.
- (iv) Four members from the Lok Sabha to be nominated by the Speaker.
- (v) Two members from the Rajya Sabha to be nominated by its Chairman.
- (vi) Five representatives of the leading Voluntary Hindi Organisations to be nominated by the Government of India.
- (vii) Five prominent workers interested in the cause of propagation of Hindi to be nominated by the Government of India.
- (viii) Joint Secretary/Joint Educational Adviser in charge of the Languages Division in the Ministry of Education.
- (ix) Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology.
- (x) Director, Central Hindi Directorate.
- (xi) One representative of the Ministry of Home Affairs.
- (xii) Chairman, Kendriya Hindi Shikshana Mandal, Agra.
- (xiii) Deputy Secretary/Deputy Educational Adviser in charge of Languages Division in the Ministry of Education—Secretary.

#### 2. Tenure

The tenure of the official and non-official members of the Samiti shall be 3 years calculated from the 1st January of the year in which the appointment is made provided that—

- (i) a member nominated under sub-clauses 1(iv), 1(v) and 1(xii) shall cease to be a member of the Samiti, as soon as he ceases to be a Member of Parliament, Chairman of the Kendriya Hindi Shikshana Mandal, Agra as the case may be;
- (ii) the ex-officio members of the Samiti shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti;
- (iii) other nominated members shall hold office during the pleasure of the Government of India; and
- (iv) if a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death etc. of a member, the member appointed in that vacancy shall hold office for the residue of the tenure of three years.

3. *Functions*

The Samiti shall advise the Government of India on :

- (i) matters of policy pertaining to the propagation and development of Hindi in the country;
- (ii) patterns of Hindi education at different levels, standardisation of syllabi and co-ordination of courses of study in Hindi including courses of Hindi Teachers Training Institutions, qualifications of Hindi teachers and arrangements for training of Hindi teachers for non-Hindi speaking States;
- (iii) methods to be adopted for improvement of the Hindi Teachers' Training Colleges opened in the various non-Hindi-speaking States with the assistance of the Central Government;
- (iv) recognition of Hindi examinations conducted by the various Voluntary Hindi Organisations in the country;
- (v) co-ordination of the activities of the various official and non-official organisations working for the propagation of Hindi in the non-Hindi speaking States; and
- (vi) selection of Hindi books for free distribution to school, college and public libraries in the non-Hindi speaking States.

4. *Standing Committees of the Samiti*

In order to enable the Samiti to discharge its various functions effectively, it may appoint some Standing Committees for specific purposes, of which the following three are essential :

- (i) Standing Committee for development of Hindi;
- (ii) Standing Committee for propagation of Hindi; and
- (iii) Standing Committee for Hindi teaching and Examinations.

The Standing Committees shall ordinarily consist of not more than 7 members to be nominated by the Chairman. The Committees shall, however, have the power of co-opting persons, who are either members or even non-members of the Samiti, but possess specialist knowledge and experience of the problems.

## ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Administrations, Prime Minister's Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha, Rajya Sabha Secretariats, Planning Commission, President's Secretariat and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. S. CHITKARA, Dy. Educational Adviser.

New Delhi, the 6th November 1965

No. 22(31)/60-SR.II.—The Government of India have decided to set up a National Committee for History of Sciences consisting of the following :—

1. Dr. D. M. Bose, Chairman  
Director,  
Bose Institute,  
93/1, Acharya Prafulla Chandra Road,  
Calcutta-9.
2. Dr. Jeen Filliozat,  
Director,  
Institute of Indology,  
Pondicherry.
3. Dr. R. C. Majumdar,  
No. 4, Bipin Pal Road,  
Calcutta-26.
4. Prof. Nurul Hasan,  
Professor of History,  
Aligarh University,  
Aligarh.
5. Prof. K. K. Pillai,  
Professor of History,  
University of Madras,  
Madras.
6. Prof. P. Ray,  
Former Professor of Chemistry,  
50/1, Hindusthan Park,  
Ballygunge,  
Calcutta.
7. Dr. A. Rehman,  
Council of Scientific and Industrial Research,  
Rafi Marg,  
New Delhi.
8. Prof. Satish Chandra,  
Professor of History,  
University of Rajasthan,  
Jaipur.

9. Prof. B. R. Seshachar,  
Professor of Zoology,  
University of Delhi,  
Delhi.
10. Prof. G. R. Sharma,  
Professor of History,  
Allahabad University,  
Allahabad.
11. Prof. R. S. Sharma,  
Professor of History,  
University of Patna,  
Patna.
12. Dr. D. V. Subba Reddi,  
Professor of History of Medicine,  
Osmania Medical College,  
Hyderabad.

The functions of the Committee will be to promote and co-ordinate the study of various branches of history of sciences, more specially in relation to their international requirements.

M. M. MALHOTRA, Dy. Secy.

## MINISTRY OF TRANSPORT

## (Transport Wing)

## MERCHANT SHIPPING

## RESOLUTIONS

New Delhi, the 5th November 1965

No. 39-MD(40)/63.—In pursuance of the Resolution of the Government of India in the Ministry of Transport and Communication (Department of Transport) No. 39-MS(5)/58, dated the 4th September 1958, as amended from time to time, the Central Government is pleased to reconstitute the following Regional Advisory Committees for Sailing Vessels as shown below for a period of two years with effect from the date of this Resolution :—

I. *Regional Advisory Committee, Jamnagar*

1. Principal Officer, Chairman  
Mercantile Marine Department, Bombay.
2. Regional Officer (Sails), Vice-Chairman  
Jamnagar.
3. Assistant Collector of Customs, Rajkot.
4. Assistant Director General (International Health),  
Directorate General of Health Services, New Delhi.
5. Port Officer (Beds) (Port Administration).
6. Port Officer, Okha (Marine Section).
7. Director of Technical Education, (Technical Education Department), Government of Gujarat.
8. Dr. Jayant H. Khatri, Kutch—Mandvi.
9. Shri Chunilal C. Khapandi, Veraval.
10. Shri ethalal Rughnath, Jamnagar.
11. Shri Abdul Rehman Imbrahim Bekar, Veraval.
12. Shri Girdharilal Dayal Bhai Shah, Porbander.
13. Shri Devjibhai Jethabhai, Jamnagar.
14. Shri Bhupat Rai Jagjivandas Sangvi, Veraval.
15. Shri Naran Damji Zala, Mandvi (Kutch).
16. Shri Moosabhai Haji Jusub, Sikka.
17. Shri Kanani Haridas Jannadas, M.L.A.
18. Shri Chhotalal Tribhovandas, M.L.A.

II. *Regional Advisory Committee, Bombay*

1. Principal Officer, Chairman  
Mercantile Marine Department, Bombay.
2. Regional Officer (Sails), Vice-Chairman  
Bombay.
3. Chief Inspector of Preventive Services, New Customs House, Bombay.
4. Assistant Director General (International Health),  
Directorate General of Health Services, New Delhi.
5. Assistant Manager (Bunders), Bombay Port Trust (Port Administration).
6. Assistant Port Officer, Bandra, Ports Organisation Maharashtra State (Marine Section).
7. Joint Director, Technical Education in Mysore, Bangalore.
8. Shri G. S. Surve, Mandiv, Ratnagiri.
9. Hagi B. Chayabba, Mangalore.
10. Shri R. R. Prabhu, Ankola, Dist. North Kanara.
11. Shri Eliyas H. Huseen, Bombay.
12. Shri C. J. Japee, Cop. L'Union Fire and Accident General Insurance Co. Limited, Bombay.
13. Shri Dharamsi D. Joshi, Bombay.
14. Shri D. R. Pandit, Mangalore, Dist. South Kanara.
15. Shri A. S. Halbe, Bulsar, Surat District.
16. Shri Pandurang Jagannath Pednekar, Bombay.
17. Shri S. M. Thakare, M.L.A.
18. Shri M. Srinivasanaik, M.L.A.

## III. Regional Advisory Committee, Tuticorin

1. Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras. *Chairman*
2. The Regional Officer (Sails), Tuticorin. *Vice-Chairman*
3. Superintendent of Central Excise, Tuticorin.
4. Assistant Director General (International Health), Directorate General of Health Services, New Delhi.
5. Port Officer, Tuticorin.
6. Port Officer, Calicut.
7. Director of Technical Education, Trivandrum.
8. Shri C. Machade, Tuticorin.
9. Shri S. N. Mohamed, Calicut.
10. Shri S. Vincent Fernandez, Tuticorin.
11. Shri Kuriyama Kantakath Assanar Kutty, Ponnani.
12. Shri Seesaya Morais, Tuticorin.
13. Shri Kunhirayan Kutty Kanagath Kunhan Bhava, Ponnani.
14. Shri R. V. Legarajulu, Madras.
15. Shri P. S. T. S. Thiraviarathanam, Tuticorin.
16. Shri Ramniklal Jannadas, Calicut.
17. Shri A. P. C. Veerababu, M.L.A.
18. Shri Antony D'cruz, M.L.A.

## IV. Regional Advisory Committee, Masulipatnam

1. Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras. *Chairman*
2. Regional Officer (Sails), Masulipatnam. *Vice-Chairman*
3. Assistant Collector of Central Excise, Vijayawada.
4. Assistant Director General (International Health), Directorate General of Health, Services, New Delhi.
5. Assistant Engineer, Marine, Kakinada.
6. Director of Technical Education, (Technical Education Department), Government of Andhra Pradesh.
7. Port Officer, Cuddalore.
8. Shri Jaldu Venkata Sreekrishna Bapna Rao, Masulipatnam.
9. Shri A. Agathiappan—Portonovo.
10. Shri Jaldu Rama Rao, Masulipatnam.
11. Shri Tirumani Narasinha Rao, Bandar.
12. Shri Makam Venkata Subbiah Nagappa Setty, Madras.
13. Shri V. Vasudevan, Cuddalore.
14. Shri Vemuri Venkata Ratnam, Masulipatnam.
15. Shri Santhanam Mudaliar Thomas, Nagapattinam.
16. Shri Temmu Tatayya, Buder Fort.
17. Shri K. S. G. Haja Shariff, M.L.A.
18. Shri Dantu Bhaskara Rao, M.L.A.

2. The Directorate General of Shipping may co-opt additional members on any of the Regional Advisory Committees, as and when considered necessary.

No. 39-MD(40)/63.—In pursuance of the Resolution of the Government of India in the Ministry of Transport and Communications (Department of Transport) No. 39-MS(5)/58, dated the 4th September 1958, as amended from time to time, the Central Government is pleased to reconstitute the Central Advisory Committee for Sailing Vessels as shown below for a period of two years with effect from the date of issue of this Resolution :—

*Chairman*

1. Director General of Shipping, Bombay.

*Vice-Chairman*

2. Senior Deputy Director General of Shipping, Bombay.

*Members*

3. Deputy Director General of Shipping in charge of Sailing Vessels;
4. Nautical Adviser to the Government of India;
5. Chief Surveyor with the Government of India (to be co-opted as and when necessary);
6. Principal Officer, Mercantile Marine Department, Bombay;
7. Flag Officer, Indian Navy, Bombay;
8. Director of Ports, Government of Gujarat, Ahmedabad;
9. Chief Ports Officer, Government of Maharashtra, Bombay;
10. State Port Officer, Government of Mysore, Mangalore;
11. State Port Officer, Government of Kerala, Trivandrum;
12. State Port Officer, Government of Madras, Madras.
13. State Port Officer, Government of Andhra Pradesh, Kakinada;
14. Port Officer, Government of Orissa, Paradeep;

15. Principal Officer, Mercantile Marine Department, Calcutta representing the Government of West Bengal.
16. Shri B. Rajagopala Rao, Member, Lok Sabha.
17. Smt. Nandini Satpathi, Member, Rajya Sabha.
18. Shri Damodar Mathuradas Ashar, Bombay.
19. Shri Premji V. Khokhari, Porbandar.
20. Dr. Jayant H. Khatri, Kutch-Mandvi.
21. Shri Damodar Morarji Parekh, Salya.
22. Shri Haji V. Chhyabba, Mangalore.
23. Shri Ishwarlal Gulabbhai Desai, Surat.
24. Shri S. M. Mohamed, Kozhikode.
25. Shri C. I. R. Machade, Tuticorin.
26. Shri K. Agathiappan, Portonovo.
27. Shri M. V. Sastry, Masulipatnam.

No. 39-MD(40)/63.—In the Resolution of the Government of India in the Ministry of Transport and Communications (Department of Transport) No. 39-MS(5)/58, dated the 4th September 1958, against item I Central Advisory Committee, under the head "Non-Government Members", the existing item No. 2 may be amended to read as follows :

2. One representative each of the All India Sailing Vessels Industries Association, Bombay and Federation of All India Sailing Vessels Industry Association, Porbandar.

NAGENDRA SINGH, Secy.

## (Roads Wing)

## RESOLUTION

New Delhi, the 30th October 1965

No. PL-4(10)/64.—In pursuance of para 5 of the late Ministry of Transport and Communications, Department of Transport (Roads Wing) Resolution No. PL-4(9)/59-Part II, dated the 8th August 1961, the Central Assessment Committee set up in terms of that Resolution under the aegis of the Indian Roads Congress is reconstituted as under :

- (i) The Consulting Engineer (Road Development), Ministry of Transport (Roads Wing);
- (ii) The President, Indian Roads Congress;
- (iii) The Director, Central Road Research Institute;
- (iv) & (v) Two Chief Engineers of States :—
  - (1) The Chief Engineer, Public Works Department (Buildings and Roads), Government of Madhya Pradesh;
  - (2) The Chief Engineer, Communications and Buildings, Government of Mysore;
- (vi) & (vii) Two Directors of State Road Research Laboratories :—
  - (1) The Director, U.P., P.W.D. Road Research Institute, Lucknow;
  - (2) The Director, Maharashtra Engineering Research Institute, Nasik;
- (viii) One member from a non-Governmental Organisation :
  - Shri Sujan Singh, Bungalow No. 2, Street B, Sector No. 2B, Chandigarh.

The Consulting Engineer (Road Development) shall continue to be the convenor of the Committee, and an officer of the Central Road Research Institute to be nominated by the Director, Central Road Research Institute, will act as the Secretary to the Committee.

2. In addition, as stated in para 3 of the aforesaid Resolution, while examining the road projects of a particular State, and while recommending suitable new techniques for replacing conventional ones, the Committee shall co-opt the Chief Engineer and the head of the Research Institute of that State or their representatives, if they are not already on the Committee. The Committee will also have the power to co-opt upto three experts who have special knowledge of the subject under consideration.

3. The terms of reference of the Committee will be the same as those mentioned in para 4 of the Resolution referred to in para 1 above. Further, as stated in para 5 of that Resolution, the members of the Committee, other than the Consulting Engineer (Road Development), the President of the Indian Roads Congress and the Director, Central Road Research Institute, will hold office for three years and will be eligible for re-appointment.

## ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to all State Governments/Administrations, the Planning Commission, the Ministry of Finance (T&P Division), the Ministry of Education (Department of Science), the Director-General, Council of Scientific and Industrial Research, the Director, Central Road Research Institute, the President, Indian Roads Congress, Shri Sujan Singh, Chandigarh; the Secretary, Indian Roads Congress.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

H. P. SINHA,  
Consulting Engineer (Road Development) &  
*Ex-Officio* Jt. Secy.

## MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

## RESOLUTION

New Delhi, the 10th November 1965

No. DW.V.510(3)/65.—In continuation of this Ministry Resolutions of even number dated the 28th May and 24th August 1965, Government are pleased to extent the period of submission of the report by the Technical Committee constituted to devise long-term measures for the protection of the Chitauri bund from the ravages of the river Great Gandak, up to the end of December 1965.

## ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the State Governments of Uttar Pradesh/Bihar/Prime Minister's Secretariat/the Private and Military Secretary to the President/the Comptroller & Auditor General of India/Planning Commission, for information.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments of Uttar Pradesh and Bihar be requested to publish it in the State Gazette for general information.

P. R. AHUJA, Jt. Secy.

## MINISTRY OF WORKS, HOUSING &amp; REHABILITATION

(Department of W. & H.)

New Delhi, the 6th May 1963

(As amended upto the 30th June 1965)

No. S. O. 1330.—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the President is pleased to make the following further amendment to the Supplementary Rules issued with the Government of India Finance Department letter No. 104-CSR, dated the 4th February, 1922 namely:—

In part VIII of the said Rules for Division XXVI-B, the following shall be substituted:—

## "Division XXVI-B

Allotment of residences under the administrative control of the Director of Estates to officers employed in eligible offices who are required to reside on duty in Delhi with the Government of India or the Delhi Administration.

*Short title and application*—S.R.317-B-1.—(1) The rules in this Division may be called the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963.

(2) They shall come into force on the 15th day of May 1963.

*Definition*—S.R. 317-B-2.—In these rules, unless the context otherwise requires:—

- (a) 'allotment' means the grant of a licence to occupy a residence in accordance with the provisions of these rules;
- (b) 'allotment year' means the year beginning on 1st January or such other period as may be notified by the President;
- (c) 'Delhi' means the Union Territory of Delhi;
- (d) 'Director of Estates' means the Director of Estates to the Government of India and includes an Additional, Deputy and Assistant Director of Estates;
- (e) 'eligible office' means a Central Government Office the staff of which has been declared by the Central Government as eligible for accommodation under these rules.
- (f) 'emoluments' means the emoluments as defined in Fundamental Rule 45-C, but excluding the compensatory allowances.

*Explanation*.—In the case of an officer who is under suspension the emoluments drawn by him on the first day of the allotment year in which he is placed under suspension, or if he is placed under suspension on the first day of the allotment year, the emoluments drawn by him immediately before that date shall be taken as emoluments.

- (g) 'family' means the wife or husband, as the case may be, and children, step-children, legally adopted children, parents, brothers or sisters as ordinarily reside with and are dependent on the officer.
- (h) 'Government' means the Central Government unless the context otherwise requires.
- (i) 'priority date' of an officer in relation to a type of residence to which he is eligible under the provisions of S.R. 317-B-5 means the earliest date from which he has been continuously drawing emoluments relevant to a particular type or a higher type in a post under the Central Government except for periods of leave:

Provided that in respect of a Type II, Type III or Type IV residence, the date from which the officer has been continuously in service under Central Government shall be his priority for that type.

Provided further that in the case of an officer on deputation to foreign service on his reposting in an eligible office in Delhi, the period of foreign service shall be included for the purpose of determination of his priority date.

Provided also that where the priority date of two or more officers is the same, seniority among them shall be determined by the amount of emoluments, the officer in receipt of higher emoluments taking precedence over the officer in receipt of lower emoluments; and where the emoluments are equal by the length of service under the Central Government.

- (j) 'rent' means the sum of money payable monthly in accordance with the provisions of the Fundamental Rules in respect of a residence allotted under these rules;
  - (k) 'residence' means any residence for the time being under the administrative control of the Director of Estates.
  - (l) 'Subletting' includes sharing of accommodation by an allottee with another person with or without payment of rent by such other person.
- Explanation*.—Any sharing of accommodation by an allottee with close relations shall not be deemed to be subletting.
- (m) 'temporary transfer' means a transfer which involves an absence for a period not exceeding four months.
  - (n) 'transfer' means a transfer from Delhi to any other place or from an eligible office to an ineligible office in Delhi and includes a transfer or reversion to service under a State Government or Union Territory Administration other than Delhi Administration.
  - (o) 'Type' in relation to an officer means the type of residence to which he is eligible under S.R. 317-B-5.

*Ineligibility of officers owning houses for allotment under these rules*, S.R. 317-B-3.—(1) In this rule,

- (a) 'house', in relation to an officer or member of his family, means a residential houses or part thereof situated in Delhi within sixteen kilometers of the place of duty of the officer by shortest route;
- (b) 'member of family', in relation to an officer, means the wife or husband or a dependent child of the officer.

(2) No officer shall be eligible for allotment of Government accommodation under these rules or, if he is already in occupation of such accommodation to its continued retention, if—

- (a) he owns, or has, since the allotment of Government accommodation, become the owner, whether in his own name or in the name of any other person, of a house;
- (b) any member of his family owns, or has, since the allotment of Government accommodation, become the owner of a house;

(3) If, after Government accommodation has been allotted to an officer, he becomes the owner of a house either in his own name or in the name of any other person, or a member of his family becomes the owner of a house, such officer shall—

- (i) notify that fact to the Director of Estates within a period of seven days from the date he or any member of his family becomes such owner; and
- (ii) either surrender the Government accommodation within that period or pay the standard rent for that accommodation as calculated under F.R. 45-B or the pooled standard rent under F.R. 45-A, whichever is higher, with effect from the date referred to in clause (i):

Provided that if such officer fails to notify the fact as provided in clause (i), his allotment of Government accommodation shall be deemed to have been cancelled with effect from the date he or the member of his family becomes the owner of a house;

Provided further that where an officer has been allotted Government accommodation before the 20th July 1964, and he or a member of his family became the owner of a house as aforesaid after such allotment but before that date, such officer may be allowed to retain the accommodation allotted to him by the Government if he pays—

- (a) the standard rent for that accommodation as calculated under F.R. 45-B or the pooled standard rent under F.R. 45-A, whichever is higher, with effect from the 20th July 1964, and
- (b) for the period prior to the 20th July 1964, any rent or damages or both recoverable from him in respect of the occupation of that accommodation.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) or (3), Government accommodation may be allotted to any officer, or, if he is in occupation of such accommodation, it may be allowed to be retained by him, under the provisions of F.R. 45-A, in the event of his becoming the owner of a house either in his own name or in the name of any other person or of a member of his family becoming the owner of a house, in the following cases, namely:—

- (a) where the house is or becomes vested in a trust created by the officer after obtaining the permission of the Government under the Conduct Rules applicable to him;
- (b) where the house belongs to the officer as a member of a Hindu undivided family and the Director of Estates is satisfied that partition of the house by metes and bounds is not feasible to make it fit for an independent residence;
- (c) if the plinth area of the house is less than one-third of the plinth area of the house of the type to which the officer is eligible under S.R. 317-B-5.

*Explanation I.*—In this rule, an officer is said to own a house in the name of any other person if the officer has acquired or transferred a house in the name of such other person—

- (i) without intending thereby to benefit such other persons; and
- (ii) the officer is in actual or constructive possession of the house or enjoys its rents or profits.

*Explanation II.*—For the purposes of this rule, an officer shall be deemed to be the owner of a house if he is in possession thereof under an agreement of sale although the title has not been conveyed to him.

*Allotment to husband and wife, Eligibility in cases of officers who are married to each other, S.R. 317-B-4.*—(1) No officer shall be allotted a residence under these rules if the wife or the husband, as the case may be, of the officer has already been allotted a residence, unless such residence is surrendered:

Provided that this sub-rule shall not apply where the husband and wife are residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by any court.

(2) Where two officers in occupation of separate residences allotted under these rules marry each other, they shall within one month of the marriage surrender one of the residences.

(3) If a residence is not surrendered as required by sub-rule (2) the allotment of the residence of the lower type shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period and if the residences are of the same type the allotment of such one of them as the Director of Estates may decide shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period.

(4) Where both husband and wife are employed under the Central Government, the title of each of them to allotment of a residence under these rules shall be considered independently.

*Classification of residences, S.R. 317-B-5.*—Save as otherwise provided by these rules, an officer will be eligible for allotment of a residence of the type shown in the table below:—

Type of residence	Category of officer or his monthly emoluments as on the first day of the allotment year in which the allotment is made.
I	Less than Rs. 100.
II	Less than Rs. 250 but not less than Rs. 110.
III	Less than Rs. 400 but not less than Rs. 250.
IV	Less than Rs. 700 but not less than Rs. 400.
V	Less than Rs. 1,300 but not less than Rs. 700.
VI	Less than Rs. 2,250 but not less than Rs. 1,300.
VII	Rs. 2,250 and above (except those eligible for Type VIII).
VIII	Officers of the status of Secretaries and Additional Secretaries to the Government of India.

*Application for allotment, S.R. 317-B-6.*—(1) An officer who seeks allotment of a residence or the continuance of allotment of a residence which has been allotted to him, may apply at any time and shall apply in that behalf to the Director of Estates when directed to do so by him and in such form and manner by such date as may be prescribed by the Director of Estates.

(2) All applications received otherwise than in pursuance of a direction under sub-rule (1) but before the 20th day of a calendar month shall be considered for allotment in the succeeding month.

*Allotment of residences and offers, S.R. 317-B-7.*—(1) Save as otherwise provided in these rules a residence on falling vacant will be allotted by the Director of Estates preferably to an applicant desiring a change of accommodation in that type under the provisions of S.R. 317-B-15 and if not required for that purpose, to an applicant without accommodation in that type having the earliest priority date for that type of residence subject to the following conditions:—

- (i) The Director of Estates shall not allot a residence of a type higher than that to what the applicant is eligible under S.R. 317-B-5.
- (ii) The Director of Estates shall not compel any applicant to accept a residence of a lower type than that to what he is eligible under S.R. 317-B-5.
- (iii) The Director of Estates, on request from an applicant for allotment of a lower category residence might allot to him a residence next below the type for which the applicant is eligible under S.R. 317-B-5 on the basis of his priority date for the same.

(2) The Director of Estates may cancel the existing allotment of an officer and allot to him an alternative residence of the same type or in emergent circumstances an alternative residence of the type next below the type of residence in occupation of the officer if the residence in occupation of the officer is required to be vacated.

(3) A vacant residence may, in addition to allotment to an officer under sub-rule (1) above, be offered simultaneously to other eligible officers in order of their priority dates.

*Maintenance of separate pools for certain categories of officers, S.R. 317-B-8.*—(1) Notwithstanding anything contained in these rules the following pools shall be maintained, namely:—

- (i) Senior Officers' Pool for officers drawing emoluments of Rs. 2,250 p.m. and above.
- (ii) Tenure Officers' Pool for the officers of the Indian Administrative Service, the Indian Police Service and gazetted officers of State Services on duty with the Central Government or the Delhi Administration on tenure basis.
- (iii) Indian Foreign Services Officers' Pool for the officers of the Indian Foreign Service posted in Delhi.
- (iv) Lady Officers' Pool for lady officers except those who are married and their husbands are eligible for allotment under these rules.

(2) The number and the type of residences to be placed in these pools shall be determined by the Government from time to time.

(3) The *Inter se* seniority of the officers eligible for allotment of residences under this rule shall be determined in the following manner, namely:—

- (a) in the Indian Foreign Service Officers' Pool or Lady Officers' Pool, on the basis of the priority date on which each such officer became eligible for the type of residence in that pool;
- (b) in the Senior Officers' Pool, on the basis of the date from which each such officer began to draw continuously the emoluments of Rs. 2,250 per month or more;
- (c) in the Tenure Officers' Pool, on the basis of the date from which each such officer is continuously holding the post under the Central Government.

*Out-of-turn allotments, S.R. 317-B-9.*—Notwithstanding the provisions of S.R. 317-B-7 allotment of a residence may be made by the Director of Estates on out-of-turn basis to an officer on grounds of serious illness of self or a member of his family in consultation, if considered necessary, with the prescribed medical authority. The priority for allotment in such cases will be the date on which the application of the officer for out-of-turn allotment is received by the Director of Estates.

*Non-acceptance of allotment or offer or failure to occupy the allotted residence after acceptance, S.R. 317-B-10.*—(1) If an officer fails to accept the allotment of a residence within five days or fails to take possession of that residence after acceptance within eight days from the date of receipt of the letter of allotment he shall not be eligible for another allotment for a period of one year from the date of the allotment letter.

(2) If an officer occupying a lower type residence allotted or offered a residence of the type for which he is eligible under S.R. 317-B-5 for which he has applied under S.R. 317-B-7 (iii), he may, on refusal of the said allotment or offer of allotment, be permitted to continue in the previously allotted residence on the following conditions, namely:—

- (a) that such an officer shall not be eligible for another allotment for a period of six months from the date of the allotment letter for the higher class accommodation;
- (b) while retaining the existing residence he shall be charged the same rent which he would have had to pay under F.R. 45-A in respect of the residence so allotted or offered or the rent payable in respect of the residence already in his occupation, whichever is higher.

is *Period for which allotment subsists and the concessional period for further retention.—S.R. 317-B-11.—(1) An allotment shall be effective from the date on which it is accepted by the officer and shall continue in force until,*

- (a) the expiry of the concessional period permissible under sub-clause (2) after the officer ceases to be on duty in an eligible office in Delhi;
- (b) it is cancelled by the Director of Estates or is deemed to have been cancelled under any provision in these rules;
- (c) it is surrendered by the officer, or
- (d) the officer ceases to occupy the residence.

(2) A residence allotted to an officer may, subject to sub-rule (3), be retained on the happening of any of the events specified in column 1 of the Table below for the period specified in the corresponding entry in column 2 thereof, provided that the residence is required for the *bona fide* use of the officer or members of his family.

TABLE

Events	Permissible period for retention of the residence
(i) Resignation, dismissal, removal or termination of service.	1 month.
(ii) Retirement or terminal leave.	2 months.
(iii) death of the allottee.	4 months.
(iv) Transfer to a place outside Delhi.	2 months.
(v) Transfer to an ineligible office in Delhi.	2 months.
(vi) On proceeding on foreign service in India.	2 Months.
(vii) Temporary transfer in India or transfer to a place outside India.	4 months.
(viii) Leave (other than leave preparatory to retirement, refused leave, terminal leave, medical leave or study leave).	For the period of leave but not exceeding 4 months.
(ix) Leave preparatory to retirement or refused leave granted under F.R. 86.	For the full period of leave on full average pay subject to a maximum of 4 months inclusive of the period, permissible in the case of retirement.
(x) Study leave or deputation outside India.	For the period of leave but not exceeding 6 months.
(xi) Study leave in India.	For the period of leave but not exceeding 6 months.
(xii) Leave on medical grounds.	For the full period of leave.
(xiii) On proceeding on training.	For the full period of training.

*Explanation.*—The period permissible on transfer mentioned against items (iv), (v), (vi) and (vii) shall count from the date of relinquishing charge plus the period of leave, if any, sanctioned to and availed of by the officer before joining duty at the new office.

(3) Where a residence is retained under sub-rule (2) the allotment shall be deemed to be cancelled on the expiry of the admissible concessional periods unless immediately on the expiry thereof the officer resumes duty in an eligible office in Delhi.

(4) An officer who has retained the residence by virtue of the concession under item (i) or item (ii) of the Table below sub-rule (2) shall, on re-employment in an eligible office within the period specified in the said Table, be entitled to retain that residence and he shall also be eligible for any further allotment of residence under these rules.

Provided that if the emoluments of the officer on such re-employment do not entitle him to the type of residence occupied by him, he shall be allotted a lower type of residence.

*Provisions relating to rent.—S.R. 317-B-12.—(1) Where an allotment of accommodation or alternative accommodation has been accepted, the liability for rent shall commence from the date of occupation or the eighth day from the date of receipt of the allotment, whichever is earlier.*

An officer who, after acceptance, fails to take possession of that accommodation within eight days from the date of receipt of the allotment letter, shall be charged rent from such date up to a period of one month or up to the date of re-allotment of that particular accommodation, whichever is earlier.

(2) Where an officer, who is in occupation of a residence is allotted another residence and he occupies the new residence, the allotment of the former residence shall be deemed to be cancelled from the date of occupation of the new residence. He may however, retain the former residence without payment of rent for that day and the subsequent day for shifting.

*Personal liability of the officer for payment of rent till the residence is vacated and furnishing of surety by temporary officers.—S.R. 317-B-13.—(1) The officer to whom a residence has been allotted shall be personally liable for the rent thereof and for any damage beyond fair wear and tear caused thereto or to the furniture, fixtures or fittings or services provided therein by Government during the period for which the residence has been and remains allotted to him, or where the allotment has been cancelled under any of the provisions in these rules, until the residence along with out-houses appurtenant thereto have been vacated and full vacant possession thereof has been restored to Government.*

(2) Where the officer to whom a residence has been allotted is neither a permanent nor a quasi-permanent Government servant, he shall execute a security bond in the form prescribed in this behalf by the Central Government with a surety, who shall be a permanent Government servant serving under the Central Government, for due payment of rent and other charges due from him in respect of such residences and services and any other residence provided in lieu.

(3) If the surety ceases to be in Government service or becomes insolvent or withdraws his guarantee or ceases to be available for any other reasons, the officer shall furnish a fresh bond executed by another surety within thirty days from the date of his acquiring knowledge of such event or fact; and if he fails to do so, the allotment of the residence to him shall, unless otherwise decided by the Director of Estates, be deemed to have been cancelled with effect from the date of that event.

*Surrender of an allotment and period of notice.—S.R. 317-B-14.—An officer may at any time surrender an allotment by giving intimation so as to reach the Director of Estates at least ten days before the date of vacation of the residence. The allotment of the residence shall be deemed to be cancelled with effect from the eleventh day after the day on which the letter is received by the Director of Estates or the date specified in the letter, whichever is latter. If he fails to give due notice he shall be responsible for payment of rent for ten days or the number of days by which the notice given by him falls short of ten days, provided that the Director of Estates may accept a notice for a short period.*

*Change of residence.—S.R. 317-B-15.—(1) An officer to whom a residence has been allotted under these rules may apply for a change to another residence of the same type or a residence of the type to which he is eligible under S.R. 317-B-5, whichever is lower. Not more than one change shall be allowed in respect of one type of residence allotted to the officer.*

(2) All applications for change made in the form prescribed by the Director of Estates and received up to the 19th day of a calendar month shall be included in the waiting list in the succeeding month. For purposes of this rule the officers whose names are included in the waiting list in an earlier month shall be senior *en bloc* to those whose names are included in the list in subsequent months. The *inter-se* seniority of the officers included in the list in any particular month shall be determined in the order of their priority dates.

(3) Changes shall be offered in order of seniority determined in accordance with sub-rule (2) and having regard to the officers' preferences as far as possible.



(4) An officer having allotment of a residence belonging to any pool mentioned in S.R. 317-B-8 shall be eligible only for a change to a residence of the same pool.

(5) If an officer fails to accept a change of residence offered to him within five days of the issue of such offer or allotment, he shall not be considered again for a change of residence of that type.

*Change of residence in the event of death of a member of the family.*—S.R. 317-B-16.—Notwithstanding anything contained in S.R. 317-B-8 or S.R. 317-B-15 an officer may be allowed a change of residence on the death of any member of his family if he applies for a change within three months of such occurrence, provided that the change will be given in the same type of residence and in the same floor as the residence already allotted to the officer.

*Mutual exchange of residences.*—S.R. 317-B-17.—Officers to whom residences of the same type have been allotted under these rules may apply for permission to mutually exchange their residences. Permission for mutual exchanges may be granted if both the officers are reasonably expected to be on duty in Delhi and to reside in their mutually exchanged residences for at least six months from the date of approval of such exchange.

*Transfer to non-family stations.*—S.R. 317-B-18.—If an officer is transferred to a station where he is not permitted or advised by Government to take his family with him and the residence allotted to him under these rules is required by the family for the *bona-fide* educational needs of his children, he may be allowed, on request, to retain the residence on payment of rent under F.R. 45-A, till the end of current academic session of his children in Delhi.

*Maintenance of residence.*—S.R. 317-B-19.—The officer to whom a residence has been allotted shall maintain the residence and premises in a clean condition to the satisfaction of the Central Public Works Department and the New Delhi Municipal Committee or the Municipal Corporation of Delhi as the case may be. Such officer shall not grow any tree, shrubs or plants contrary to the instructions issued by the Government or Central Public Works Department nor cut or lop off any existing tree or shrub in any garden, courtyard or compound attached to the residence save with the prior permission in writing of the Central Public Works Department. Trees, plantation or vegetation, grown in contravention of this rule may be caused to be removed by the Directorate of Horticulture at the risk and cost of the officer concerned.

*Subletting and sharing of residences.*—S.R. 317-B-20.—(1) No officer shall share the residence allotted to him or any of the out-houses, garages and stables appurtenant thereto except with the employees of the Central Government eligible for allotment of residences under these rules. The servant's quarters, out-houses, garages and stables may be used only for the *bona-fide* purposes including residence of the servants of the allottee or for such other purposes as may be permitted by the Director of Estates.

(2) No officer shall sublet the whole of his residence :

Provided that an officer proceeding on leave may accommodate in the residence any other officer eligible to share Government accommodation, as a caretaker, for the period specified in S.R. 317-B-11(2), but not exceeding six months.

(3) Any officer who shares or sublets his residence shall do so at his own risk and responsibility and shall remain personally responsible for any rent payable in respect of the residence and for any damage caused to the residence or its precincts or grounds or services provided therein by Government beyond fair wear and tear.

*Consequences of breach of rules and conditions.*—S.R. 317-B-21.—(1) If an officer to whom a residence has been allotted unauthorisedly sublets the residence or charges rent from the sharer at a rate which the Director of Estates considers excessive or erects any unauthorised structure in any part of the residence or uses the residence or any portion thereof for any purposes other than that for which it is meant or tampers with the electric or water connection or commits any other breach of the rules in this Division or of the terms and conditions of the allotment or uses the residence or premises or permits or suffers the residence or premises to be used for any purpose which the Director of Estates considers to be improper or conducts himself in a manner which in his opinion is prejudicial to the maintenance of harmonious relations with his neighbours or has knowingly furnished incorrect information in any application or written statement with a view to securing the allotment, the Director of Estates may, without prejudice to any other dis-

ciplinary action that may be taken against him, cancel the allotment of the residence.

*Explanation.*—In this sub-rule the expression 'officer' includes, unless the context otherwise requires, a member of his family and any person claiming through the officer.

(2) If the officer has failed to notify to the Director of Estates as provided for in sub-rule (2) of S.R. 317-B-3 or while so notifying has in any application or statement suppressed any material fact the Director of Estates may cancel the allotment with effect from the date he became ineligible for allotment of Government accommodation under sub-rule (1) of S.R. 317-B-3.

(3) If an officer sublets a residence allotted to him or any portion thereof or any of the out-houses, garages or stables appurtenant thereto, in contravention of these rules, he may, without prejudice to any other action that may be taken against him be charged enhanced rent not exceeding four times the standard rent under F.R. 45-A. The quantum of rent to be recovered and the period for which the same may be recovered in each case will be decided by the Director of Estates on merits. In addition the officer may be debarred from sharing the residence for a specified period in future as may be decided by the Director of Estates.

(4) Where action to cancel the allotment is taken on account of unauthorised subletting of the premises by the allottee, a period of sixty days shall be allowed to the allottee, and any other person residing with him therein to vacate that premises. The allotment shall be cancelled with effect from the date of vacation of the premises or expiry of the period of sixty days from the date of the orders for the cancellation of the allotment, whichever is earlier.

(5) Where the allotment of a residence is cancelled for conduct prejudicial to the maintenance of harmonious relations with neighbours, the officer at the discretion of the Director of Estates may be allotted another residence in the same class at any other place.

(6) The Director of Estates shall be competent to take all or any of the actions under sub-rules (1) to (5) of this rule and also to declare the officer, who commits a breach of the rules and instructions issued to him, to be ineligible for allotment of residential accommodation for a period not exceeding three years.

*Overstayal in residence after cancellation of allotment.*—S.R. 317-B-22.—Where, after an allotment has been cancelled or is deemed to be cancelled under any provision contained in these rules, the residence remains or has remained in occupation of the officer to whom it was allotted or of any person claiming through him, such officer shall be liable to pay damages for use and occupation of the residence, services, furniture and garden charges, equal to the market rent as may be determined by Government from time to time :

Provided that an officer, in special cases, may be allowed by the Director of Estates to retain a residence on payment of twice the standard rent under F.R. 45-A, or twice the pooled standard rent under F.R. 45-A, whichever is higher, for a period not exceeding six months beyond the period permitted under S.R. 317-B-11 (2).

*Continuance of allotments made prior to the issue of these rules.*—S.R. 317-B-23.—Any valid allotment of a residence which is subsisting immediately before the commencement of these rules under the rules then in force shall be deemed to be an allotment duly made under these rules notwithstanding that the officer to whom it has been made is not entitled to a residence of that type under S.R. 317-B-5 and all the preceding provisions of these rules shall apply in relation to that allotment and that officer accordingly.

*Interpretation of rules.*—S.R. 317-B-24.—If any question arises as to the interpretation of the rules in this Division the decision of the Government thereon shall be final.

*Relaxation of rules.*—S.R. 317-B-25.—The Government may for reasons to be recorded in writing relax all or any of the provisions of the rules in this Division in the case of any officer or residence or class of officers or type of residences.

*Delegation of powers or functions.*—S.R. 317-B-26.—The Government may delegate any or all the powers conferred upon it by the rules in this Division to any officer under its control, subject to such conditions as it may deem fit to impose.

(No. 3/1/63-Acc.)

V. P. SUD, Dy. Secy.

